पहल

सरकार ने सुशासन के एक उपाय के रूप में पहल के माध्यम से एलपीजी उपभोक्ताओं को राजसहायता प्रदान करने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली शुरू की है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य राजसहायता के दुरुपयोग को रोकने के उपाय के आधार पर राजसहायता को तर्कसंगत बनाना है न कि राजसहायता को समाप्त करना है। सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होने के नाते पहल योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल किया गया है। लागू राजसहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

पहल से 'फर्जी' खातों, एकाधिक खातों और निष्क्रिय खातों की पहचान करने में मदद मिली है। इससे राजसहायता प्राप्त एलपीजी का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए होने वाले विपथन को रोकने में भी मदद मिली है।

इसके अलावा, सरकार ने ऐसे एलपीजी उपभोक्ताओं अथवा उनके पति/पत्नी, जिनकी कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक है, को एलपीजी राजसहायता प्राप्त करने से वंचित करके राजसहायता खर्च को तर्कसंगत बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं।